रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम०, 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार 31 मार्च, 1989/10 चैत्र, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIATE

NOTIFICATION

Shimla-4, the 30th March, 1989

No. 1-8/89-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Himachal Pradesh

Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989 (Bill No. 2 of 1989), having been introduced on the 30th March, 1989 in the Himachal Pradesh Legislative Assembly is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
Secretary.

1989 का विधेयक संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1989

(विधान सभा में यथा पुरः स्थापित)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के निकालने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 1989 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए 91,60,34,000 रुपये निकालना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक धनराशियां, जिनका योग 91,60,34,000 रुपये (इकानवे करोड़, साठ लाख, चौंतीस हजार रुपये) है, वित्तीय वर्ष 1989-90 के अप्रैल मास में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित संदायों के विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, निकाली जाएं ।

विनियोग।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का विनियोग, अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में अभिव्यक्त प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	27,31,000	34,000	27,65,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	7,66,000	3,21,000	10,87,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	33,18,000	6,89,000	40,07,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	2,15,85,000	5,36,000	2,21,21,000
		(पूंजी)	2,08,000	—	2,08,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	1,21,27,000	—	1,21,27,000
		(पूंजी)	90,000	—	90,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	44,51,000	—	44,51,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	3,10,08,000	—	3,10,08,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	12,51,15,000	—	12,51,15,000
		(पूंजी)	24,62,000	—	24,62,000
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण	(राजस्व)	4,23,78,000	—	4,23,78,000
		(पूंजी)	21,78,000	—	21,78,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	4,05,33,000	—	4,05,33,000
		(पूंजी)	25,20,000	—	25,20,000
11	कृषि	(राजस्व)	3,07,39,000	—	3,07,39,000
		(पूंजी)	1,05,19,000	—	1,05,19,000
12	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	1,44,11,000	—	1,44,11,000
		(पूंजी)	1,29,58,000	—	1,29,58,000
13	भूमि और जल संरक्षण	(राजस्व)	87,85,000	—	87,85,000
		(पूंजी)	6,92,000	—	6,92,000
14	पशु पालन और दुग्ध विकास	(राजस्व)	89,52,000	—	89,52,000
		(पूंजी)	13,87,000	—	13,87,000
15	मत्स्य	(राजस्व)	10,33,000	—	10,33,000
		(पूंजी)	1,56,000	—	1,56,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	3,30,55,000	—	3,30,55,000
		(पूंजी)	5,72,000	—	5,72,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	1,71,23,000	—	1,71,23,000
		(पूंजी)	4,03,80,000	4,13,000	4,07,93,000
18	पूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	2,33,86,000	—	2,33,86,000
		(पूंजी)	51,89,000	—	51,89,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण (पोषाहार सहित)	(राजस्व)	1,63,55,000	—	1,63,55,000
		(पूंजी)	6,44,000	—	6,44,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	1,84,80,000	—	1,84,80,000
		(पूंजी)	41,000	—	41,000
21	सहकारिता	(राजस्व)	43,38,000	—	43,38,000
		(पूंजी)	42,62,000	—	42,62,000
22	खाद्य और भण्डारण	(राजस्व)	32,63,000	—	32,63,000
		(पूंजी)	1,16,96,000	—	1,16,96,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	25,83,000	—	25,83,000
		(पूंजी)	3,52,41,000	—	3,52,41,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण	(राजस्व)	27,87,000	—	27,87,000
		(पूंजी)	1,62,000	—	1,62,000
25	सड़क, जल परिवहन और नगर विमानन	(राजस्व)	1,49,69,000	—	1,49,69,000
		(पूंजी)	1,18,70,000	—	1,18,70,000
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन	(राजस्व)	13,99,000	—	13,99,000
		(पूंजी)	11,83,000	—	11,83,000
27	श्रम और रोजगार	(राजस्व)	27,69,000	—	27,69,000
		(पूंजी)	4,10,000	—	4,10,000
28	जलपूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास	(राजस्व)	3,70,88,000	—	3,70,88,000
		(पूंजी)	1,31,27,000	—	1,31,27,000
29	वित्त	(राजस्व)	4,45,00,000	7,41,70,000	11,86,70,000
		(पूंजी)	—	5,99,38,000	5,99,38,000
30	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	(पूंजी)	27,58,000	—	27,58,000
31	जन जातीय विकास	(राजस्व)	3,42,52,000	—	3,42,52,000
		(पूंजी)	1,49,49,000	—	1,49,49,000
		कुल जोड़	77,99,33,000	13,61,01,000	91,60,34,000
		(राजस्व)	60,42,79,000	7,57,50,000	68,00,29,000
		(पूंजी)	17,56,54,000	6,03,51,000	23,60,05,000

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 और 204 के अधीन विहित प्रक्रिया के पूर्ण होने तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 206 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1989-90 के अप्रैल मास के लिए अपेक्षित धन के ऐसे व्यय को जो संचित निधि पर प्रभारित है और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्यय को पूरा करने के लिए, निकालने का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है । मांगे गए धन में वर्ष 1989-90 की वस्तुतः नई स्कीमों का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

नियमित बजट विधान सभा द्वारा अप्रैल, 1989 में पारित किया जाना है । अतः अप्रैल 1989 के लिए लेखा अनुदान अभिप्राप्त करना है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :
30 मार्च, 1989.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[वित्त विभाग, फाइल सं0 फिन ए0 सी0 (1) 10/88]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1989 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किये जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

[*Authoritative English Text of the Himachal Pradesh Viniyog (Lekha Anudan) Vidheyak*, 1989 (1989 *ka Vidheyak Sankhyank* 2) *as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 2 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1989

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year 1989-90.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1989. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 91,60,34,000 (Ninety-one crores, sixty lakhs and thirty-four thousand rupees) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the month of April of the financial year 1989-90 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule. Withdrawal of Rs. 91,60,34,000 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1989-90.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* section 2 and 3)

1	2		3		
Demand No.	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	27,31,000	34,000	27,65,000
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	7,66,000	3,21,000	10,87,000
3	Administration of Justice	(Revenue)	33,18,000	6,89,000	40,07,000
4	General Administration	(Revenue)	2,15,85,000	5,36,000	2,21,21,000
		(Capital)	2,08,000	—	2,08,000
5	Land Revenue	(Revenue)	1,21,27,000	—	1,21,27,000
		(Capital)	90,000	—	90,000
6	Excise and Taxation	(Revenue)	44,51,000	—	44,51,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	3,10,08,000	—	3,10,08,000
8	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	12,51,15,000	—	12,51,15,000
		(Capital)	24,62,000	—	24,62,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	4,23,78,000	—	4,23,78,000
		(Capital)	21,78,000	—	21,78,000
10	Public Works	(Revenue)	4,05,33,000	—	4,05,33,000
		(Capital)	25,20,000	—	25,20,000
11	Agriculture	(Revenue)	3,07,39,000	—	3,07,39,000
		(Capital)	1,05,19,000	—	1,05,19,000
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	1,44,11,000	—	1,44,11,000
		(Capital)	1,29,58,000	—	1,29,58,000
13	Soil and Water Conservation	(Revenue)	87,85,000	—	87,85,000
		(Capital)	6,92,000	—	6,92,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development	(Revenue)	89,52,000	—	89,52,000
		(Capital)	13,87,000	—	13,87,000
15	Fisheries	(Revenue)	10,33,000	—	10,33,000
		(Capital)	1,56,000	—	1,56,000
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	3,30,55,000	—	3,30,55,000
		(Capital)	5,72,000	—	5,72,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	1,71,23,000	—	1,71,23,000
		(Capital)	4,03,80,000	4,13,000	4,07,93,000
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	2,33,86,000	—	2,33,86,000
		(Capital)	51,89,000	—	51,89,000
19	Social Security, Welfare (Including nutrition)	(Revenue)	1,63,55,000	—	1,63,55,000
		(Capital)	6,44,000	—	6,44,000
20	Rural Development	(Revenue)	1,84,80,000	—	1,84,80,000
		(Capital)	41,000	—	41,000

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
21	Co-operation	(Revenue)	43,38,000	—	43,38,000
		(Capital)	42,62,000	—	42,62,000
22	Food and Warehousing	(Revenue)	32,63,000	—	32,63,000
		(Capital)	1,16,96,000	—	1,16,96,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	25,83,000	—	25,83,000
		(Capital)	3,52,41,000	—	3,52,41,000
24	Stationery and Printing	(Revenue)	27,87,000	—	27,87,000
		(Capital)	1,62,000	—	1,62,000
25	Road, Water Transport and Civil Aviation	(Revenue)	1,49,69,000	—	1,49,69,000
		(Capital)	1,18,70,000	—	1,18,70,000
26	Tourism and Hospitality	(Revenue)	13,99,000	—	13,99,000
		(Capital)	11,83,000	—	11,83,000
27	Labour and Employment	(Revenue)	27,69,000	—	27,69,000
		(Capital)	4,10,000	—	4,10,000
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	3,70,88,000	—	3,70,88,000
		(Capital)	1,31,27,000	—	1,31,27,000
29	Finance	(Revenue)	4,45,00,000	7,41,70,000	11,86,70,000
		(Capital)	—	5,99,38,000	5,99,38,000
30	Loans to Government Servants	Capital)	27,58,000	—	27,58,000
31	Tribal Development	(Revenue)	3,42,52,000	—	3,42,52,000
		(Capital)	1,49,49,000	—	1,49,49,000
	Grand Total	..	77,99,33,000	13,61,01,000	91,60,34,000
	(Revenue)	..	60,42,79,000	7,57,50,000	68,00,29,000
	(Capital)	..	17,56,54,000	6,03,51,000	23,60,05,000

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly for the month of April, 1989 of the financial year 1989-90 pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes for the year 1989-90.

The regular Budget is to be passed by the Legislative Assembly in April, 1989. As such the Vote on Account is being obtained for April, 1989.

SHIMLA :
The 30th March, 1989.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department, File No. Fin. A-C (1) 10/88]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1989, recommends, under Article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।